Journal of Research and Development
A Multidisciplinary International Level Referred and Double Blind Peer Reviewed, Open Access
ISSN : 2230-9578 | Website: https://jrdrvb.org Volume-18, Issue-3(A)| March-2026

Original Article

डिजिटल इंडिया पहल और महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण

नाहिद प्रवीण
शोधार्थी, राजनीति विज्ञान विभाग
ल. ना. मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा
Email – nahiddu2225@gmail.com

Manuscript ID:
JRD -2026-180333
ISSN: 2230-9578
Volume 18
Issue 3(A)
Pp. 172-176
March- 2026
Submitted: 25 Feb. 2026
Revised: 05 Mar. 2026
Accepted: 15 Mar. 2026
Published: 31 Mar. 2026

सारांश –

डिजिटल इंडिया पहल ने 2015 में शुरू होने के बाद से भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी डिजिटल अर्थव्यवस्था बना दिया है, जो जीडीपी में 11.7 प्रतिशत का योगदान देती है, लेकिन यह मिश्रित परिणाम महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण पर भी लागू होता है। एक ओर, 83,000 से 5.50 लाख CSC केंद्रों की संख्या बढ़ी है, जिनमें से 74,000 से अधिक महिला ग्राम स्तरीय उद्यमी हैं. यशोदा एआई और कंप्यूटर सखी जैसी पहलें ग्रामीण महिलाओं को डिजिटल साक्षर बना रहे हैं। वित्तीय समावेशन सूचकांक 46 से 67 हो गया है, और महिलाओं की चुक दर 1.6% है, जबकि पुरुषों की चुक दर 2.2% है। साथ ही, महत्वपूर्ण चुनौतियाँ भी बनी हुई हैं—डिजिटल वर्कफोर्स में महिलाओं का हिस्सा केवल 20 प्रतिशत है और पुरुषों की तुलना में 82 प्रतिशत कम कमाई करती हैं; ग्रामीण महिलाओं में से केवल 48.4 प्रतिशत मोबाइल फोन रखती हैं और 37 प्रतिशत मोबाइल से इंटरनेट चलाती हैं; वित्तीय उत्पादों का उपयोग करने वाली 97 प्रतिशत महिलाएँ जानकारी की कमी से झिझकती हैं। मंडला जिला मध्य प्रदेश में 100 प्रतिशत डिजिटल साक्षरता हासिल करने वाला पहला जिला बन गया है, जो दिखाता है कि लक्षित हस्तक्षेप बदलाव ला सकते हैं। इसलिए, महात्मा गांधी की दृष्टि में, "स्त्री और पुरुष एक ही सिक्के के दो पहलू हैं", को साकार करने के लिए ताकि महिलाएँ केवल डिजिटल इंडिया की उपभोक्ता न रहें, बल्कि इसकी रचनाकार और निर्णय-निर्माता भी बन सकें, डिजिटल इंडिया को अब समावेशी *AI* डिजाइन, समान वेतन, वित्तीय स्वायत्तता और नेतृत्व की भूमिकाओं को सुनिश्चित करने की दिशा में आगे बढ़ना होगा।

कीवर्ड: *डिजिटल इंडिया, महिला आर्थिक सशक्तिकरण, ग्रामीण महिला सशक्तिकरण, डिजिटल साक्षरता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, महिला डिजिटल वर्कफोर्स, लैंगिक समानता, आत्मनिर्भरता, महिला उद्यमिता*

प्रस्तावना:

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2015 में शुरू की गई डिजिटल इंडिया पहल ने भारत को एक डिजिटल सशक्त समाज और ज्ञान अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा। दस साल में, यह पहल भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी डिजिटल अर्थव्यवस्था बनाने में सफल रही है. यह देश के सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में 11.7 प्रतिशत का योगदान देता है, और 2030 तक यह 20 प्रतिशत से अधिक होगा।[1] इस डिजिटल बदलाव की केंद्रीय चिंता है: क्या सभी लोग, खासकर महिलाएं, इस डिजिटल क्रांति से समान लाभ ले रहे हैं? क्या "सबका साथ, सबका विकास" डिजिटल इंडिया का लक्ष्य वास्तव में महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाया है?

महात्मा गांधी ने कहा, "स्त्री और पुरुष एक ही सिक्के के दो पहलू हैं..।" एक के बिना दूसरा नहीं हो सकता। "दोनों का विकास समान होना चाहिए" ।[2] इस गांधीवादी दृष्टि को साकार करने का एक उपाय है डिजिटल इंडिया पहल—एक ऐसा समाज जहाँ महिलाओं और पुरुषों को डिजिटल उपकरणों, वित्तीय सेवाओं और आर्थिक अवसरों तक समान पहुँच है।

Creative Commons (CC BY-NC-SA 4.0)
This is an open access journal, and articles are distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International Public License, which allows others to remix, tweak, and build upon the work noncommercially, as long as appropriate credit is given and the new creations ae licensed under the idential terms.

Address for correspondence:
नाहिद प्रवीण,शोधार्थी, राजनीति विज्ञान विभाग ल. ना. मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा

How to cite this article:
प्रवीण, . नाहिद. (2026). डिजिटल इंडिया पहल और महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण. Journal of Research & Development, 18(3(A)), 172–176. https://doi.org/10.5281/zenodo.19641846

Quick Response Code:
Website:
https://jrdrvb.org/
DOI:
10.5281/zenodo.19641846

Journal of Research and Development
A Multidisciplinary International Level Referred and Double Blind Peer Reviewed, Open Access
ISSN : 2230-9578 | Website: https://jrdrvb.org Volume-18, Issue-3(A)| March-2026

डिजिटल इंडिया—दशक भर की उपलब्धियाँ:

1. **डिजिटल इंडिया की यात्रा-** 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिजिटल इंडिया कार्यक्रम शुरू किया, जो प्रौद्योगिकी को हर भारतीय के लिए उपलब्ध कराना चाहता था । डिजिटल बुनियादी ढाँचे का विस्तार, ई-गवर्नेंस सेवाओं का विस्तार और डिजिटल साक्षरता अभियान इस पहल का हिस्सा थे।

भारत ने इस दशक में काफी प्रगति की है। डिजिटल अर्थव्यवस्था का जीडीपी में योगदान 11.7 प्रतिशत है, जो 2030 तक 20 प्रतिशत से अधिक होने का अनुमान है UPI भुगतान, जो भारत की डिजिटल क्षमताओं का वैश्विक प्रमाण है, वीज़ा लेनदेन को पीछे छोड़ दिया है ।[3]

2. **CSC का विस्तार और महिला उद्यमिता-** CSC का विस्तार डिजिटल इंडिया की सबसे बड़ी सफलताओं में से एक है। 2014 में केवल 83,000 CSC केंद्र थे, लेकिन आज लगभग 5.50 लाख हैं। ये केंद्र ग्रामीण इलाकों में डिजिटल सेवाओं की आपूर्ति में महत्वपूर्ण हैं।

विशेष रूप से, इन केंद्रों का संचालन 74,000 से अधिक महिला ग्राम स्तरीय उद्यमी (VLE) कर रहे हैं, जो सशक्तिकरण के नए मानदंड स्थापित कर रहे हैं। “CSC, डिजिटल इंडिया के एक मॉडल के रूप में उभरा है जो समावेशन और सशक्तिकरण के एक नए प्रतिमान का प्रतिनिधित्व करता है,” श्री संजय राकेश, CSC SPV के प्रबंध निदेशक और CEO ने कहा ।[4]

3. **डिजिटल शिक्षा में महिलाओं की भागीदारी-** डिजिटल इंडिया ने शिक्षा क्षेत्र में महिलाओं के लिए नए अवसर खोल दिए हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय के लेडी श्री राम कॉलेज फॉर वीमेन में डिजिटल इंडिया जागरूकता कार्यशाला में डिजीलॉकर, साइबर सुरक्षा, यूमैंग, माईस्कीम, ओपन फोर्ज और अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स (ABC) जैसे महत्वपूर्ण पहलों पर चर्चा हुई।[5] ऐसे कार्यशालाएँ युवा महिलाओं को डिजिटल उपकरणों से लैस करने में महत्वपूर्ण हैं।

उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मदद फाउंडेशन और सामाजिक कल्याण विभाग के सहयोग से डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम शुरू किया है। गोरखपुर और महाराजगंज के जय प्रकाश नारायण सर्वोदया बालिका विद्यालयों में चालिस टैबलेट बांटे गए हैं। राज्य मंत्री असीम अरुण ने कहा, "आज की तेजी से बदलती दुनिया में डिजिटल शिक्षा एक महत्वपूर्ण आवश्यकता बन गई है। “आधुनिक तकनीकी उपकरणों तक पहुँच बालिका छात्रों की शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाएगी, उन्हें आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता भी मिलेगी” ।[6]

वित्तीय समावेशन—महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता का आधार:

1. **वित्तीय समावेशन में प्रगति-** वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना डिजिटल इंडिया का एक प्रमुख लक्ष्य रहा है। 2018 में 46.0 था, लेकिन 2025 तक भारत का वित्तीय समावेशन सूचकांक 67.0 हो जाएगा। बैंकिंग सेवाओं, डिजिटल भुगतान और सरकारी योजनाओं में सुधार का यह परिणाम है। महिलाएँ लगभग 47 प्रतिशत इंटरनेट उपयोगकर्ताओं का हिस्सा बन गई हैं, जो डिजिटल पहुँच में लैंगिक अंतर को कम करने की ओर एक अच्छा संकेत है।

2. **महिलाओं के लिए अप्रयुक्त आर्थिक अवसर-** RedSeer Strategy Consultants की एक रिपोर्ट के अनुसार, बैंकिंग, वित्तीय सेवाओं और बीमा (BFSI) क्षेत्र में लगभग 7.5 करोड़ कार्यरत महिलाएँ लगभग 2.8 लाख करोड़ रुपये का अप्रयुक्त बाजार अवसर प्रदान करती हैं। यह आँकड़ा बताता है कि महिलाओं की आर्थिक क्षमता अभी तक पूरी तरह से नहीं प्रयोग की गई है। किंतु पैसे अपनाने और डिजिटल पहुँच के बीच एक महत्वपूर्ण अंतर है। महिलाएँ लगभग 23 प्रतिशत म्यूचुअल फंड परिसंपत्तियों, 13 प्रतिशत क्रेडिट कार्ड बकाया और केवल 17 प्रतिशत सक्रिय व्यक्तिगत ऋण का हिस्सा हैं।

3. **जानकारी की कमी—एक प्रमुख बाधा :** रिपोर्ट में सूचना की कमी को एक महत्वपूर्ण बाधा बताया गया है। सर्वेक्षण में शामिल 97 प्रतिशत महिलाओं ने बताया कि वे नए वित्तीय उत्पादों के प्रति जानकारी की कमी से परेशान हैं। यह बताता है कि सिर्फ डिजिटल पहुँच देना पर्याप्त नहीं है; इसके साथ ही वित्तीय साक्षरता कार्यक्रमों की जरूरत है।

4. **महिलाएँ—बेहतर उधारकर्ता :** सकारात्मक पक्ष यह है कि महिला उधारकर्ता ऋण देने में बेहतर हैं। प्राइम या उच्च क्रेडिट स्कोर श्रेणी में लगभग 66% महिलाएँ हैं, जबकि 60% पुरुष हैं। पुरुषों की तुलना में महिलाओं की चूक दर भी कम है—1.6 प्रतिशत से 2.2 प्रतिशत की वृद्धि।[7]

RedSeer Strategy Consultants के पार्टनर जसबीर एस. जुनेजा ने कहा “महिलाएँ BFSI में उच्चतम गुणवत्ता वाले समूहों में से एक के रूप में उभर रही हैं—अनुशासित उधारकर्ता, सुसंगत बचतकर्ता, और लक्ष्य-उन्मुख निवेशक,” । यह निष्कर्ष बताता है कि डिजिटल वित्तीय सेवाओं में महिलाओं के लिए लक्षित हस्तक्षेप की जरूरत है।

5. **पारिवारिक प्रभाव और स्वायत्तता :** लगभग 84 प्रतिशत महिलाएँ वित्तीय सलाह के लिए अपने परिवार पर निर्भर करती हैं। डिजिटल इंडिया के सशक्तिकरण लक्ष्यों के लिए एक चुनौती है कि पारिवारिक कारणों से महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता सीमित हो सकती है। लगभग 93 प्रतिशत महिलाएँ बचत करती हैं और 56 प्रतिशत अपने वित्तीय निर्णयों को शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं और दीर्घकालिक सुरक्षा से जोड़ती हैं। उच्च जोखिम वाली रिटर्न-अधिकतम निवेश रणनीतियों को प्राथमिकता दी जाती है, जो केवल दस प्रतिशत से कम हैं।[8]

डिजिटल वर्कफोर्स में महिलाएँ—अवसर और चुनौतियाँ :

1. **डिजिटल वर्कफोर्स में महिलाओं की भागीदारी -** Krea विश्वविद्यालय के अनुसंधान केंद्र LEAD और द/नज इंस्टीट्यूट द्वारा जारी की गई रिपोर्ट, "डिकोडेड: वीमेन एंड द फ्यूचर ऑफ डिजिटल वर्क इन इंडिया" के अनुसार, महिलाएँ भारत के डिजिटल वर्कफोर्स का केवल एक-पाँचवाँ हिस्सा, या लगभग 20 प्रतिशत, हैं, और बहुत कम महिलाएँ डेटा और प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में निर्णायक या नेतृत्व।

रिपोर्ट डिजिटल कार्य परिदृश्य को तीन खंडों में वर्गीकृत करती है:

प्रथम, डिजिटली-ऑगमेंटेड लाइवलीहुड्स: पारंपरिक नौकरियाँ जहाँ महिलाएँ डिजिटल उपकरणों का उपयोग करती हैं, जैसे किसानों को AI-आधारित फसल सलाह देना या स्वयं सहायता समूह के सदस्य मोबाइल भुगतान का उपयोग करना।

द्वितीय, डिजिटली-इनेबल्ड वर्क: ऐप-आधारित और फ्रंटलाइन भूमिकाएँ जहाँ सेवा वितरण और डिजिटल उपकरणों का समन्वय केंद्रीय है।

तृतीय, डिजिटली-एम्बेडेड वर्क: ऐसे काम जो डिजिटल प्रौद्योगिकियों से आए हैं, जैसे डेटा एनोटेशन, सामग्री मॉडरेशन और कृत्रिम बुद्धि के मॉडल प्रशिक्षण।

2. **वेतन असमानता और नौकरी की गुणवत्ता -** रिपोर्ट में एक चिंताजनक तथ्य सामने आया है कि महिलाएँ पुरुषों की तुलना में लगभग 82 प्रतिशत अधिक कमाती हैं, जो लैंगिक असमानताओं को वेतन और प्रगति में दिखाता है। गिग वर्कर्स में लगभग 28 प्रतिशत महिलाएं हैं, जो अधिकतर देखभाल, सौंदर्य और घरेलू सेवाओं में काम करती हैं। AI और डेटा वैल्यू चेन में, टियर-2 और टियर-3 शहरों में एंट्री-लेवल वर्कर्स का 40-50 प्रतिशत महिलाएं हैं ।[9]

रिपोर्ट बताती है कि महिलाओं को अस्पष्ट या अपारदर्शी एल्गोरिदम, अनौपचारिक कार्य अनुबंधों और ऑनलाइन मॉडरेशन नौकरियों के दौरान जोखिम का सामना करना पड़ता है, जो भावनात्मक तनाव और वित्तीय असुरक्षा का कारण बन सकता है।

3. **दूरस्थ कार्य: एक सशक्तिकरण उपकरण -** रिपोर्ट ने पाया कि भुगतान वाले काम को देखभाल की जिम्मेदारियों के साथ संतुलित करने में लचीलापन देने वाले दूरस्थ और हाइब्रिड मॉडल महिलाओं के लिए विशेष रूप से फायदेमंद रहे हैं। महिला-नेतृत्व वाले नेटवर्क और सामुदायिक डिजिटल हब ने भी डिजिटल आत्मविश्वास और सहकर्मी शिक्षा को बनाया है। जिन संगठनों ने चाइल्डकेयर सुविधाओं, सुरक्षित परिवहन और मेंटरशिप कार्यक्रमों में निवेश किया है, उनमें महिलाओं के बने रहने और विकसित होने की दर अधिक हुई है।

4. **लगातार बनी हुई बाधाएँ -**

रिपोर्ट में उन बाधाओं को भी रेखांकित किया गया है जो प्रगति को रोक रही हैं:

- कई महिलाओं को बुनियादी भागीदारी से आगे बढ़ने से रोकने वाले दो कारकों में से एक सीमित डिवाइस पहुँच है और दूसरा है कम डिजिटल साक्षरता।
- महिलाओं की डिजिटल नौकरी को बनाए रखने और आगे बढ़ाने की क्षमता को गहरी जड़ें जमाए सामाजिक मानदंड, अवैतनिक देखभाल का बोझ और गतिशीलता की कमी ने और सीमित कर दिया है।

ग्रामीण महिलाओं में केवल 48.4 प्रतिशत मोबाइल फोन रखते हैं, जबकि पुरुषों में 80.7 प्रतिशत ऐसा करते हैं। महिलाओं में से केवल 37% मोबाइल इंटरनेट का उपयोग करती हैं। डिजिटल अर्थव्यवस्था में महिलाओं की भागीदारी में यह डिजिटल विभाजन एक प्रमुख बाधा है।[10]

डिजिटल सशक्तिकरण की जमीनी पहलें :

1. **कंप्यूटर सखी: राजस्थान में एक मॉडल -** राजस्थान के चूरू जिले में जिला कलेक्टर सिद्धार्थ सिहाग की अगुवाई में चलने वाला कार्यक्रम "कंप्यूटर सखी" ग्रामीण महिलाओं के डिजिटल सशक्तिकरण का एक उदाहरण बन गया है। सिहाग के अनुसार, सरकारी स्कूल प्रयोगशालाओं में प्रशिक्षण प्राप्त कर चुकी लगभग 6,500 महिलाओं के लक्ष्य बहुत बड़े हैं। चूरू जिले में 532 स्कूल हैं, सभी में कंप्यूटर शिक्षक और कक्षाएं हैं। अगले छह महीनों में जिला प्रशासन का लक्ष्य 25,000 से 30,000 महिलाओं को प्रशिक्षित करना है।

सभी स्कूलों में वर्ष के अंत तक कंप्यूटर लैब होंगे। सिहाग ने कहा कि उनमें जल्द ही इंटरनेट कनेक्टिविटी भी होगी, बताते हुए कि उनके पास 70,000 महिलाएँ स्वयं सहायता समूहों (SHGs) से जुड़ी हुई हैं। हमारा उद्देश्य उन्हें डिजिटल और वित्तीय ज्ञान देना है ताकि वे समाज में सकारात्मक योगदान दे सकें। सरकारी स्कूल जिला प्रशासन कार्यक्रम को अंतिम रूप देने के लिए कंप्यूटर लैब का उपयोग कर रहा है। “हम मौजूदा बुनियादी ढाँचे का उपयोग कर रहे हैं, जिसमें कोई अतिरिक्त खर्च नहीं होता।” इस कार्यक्रम से प्रशिक्षित महिलाएँ खुश हैं। चूरू जिले के बीदसादर निवासी 30 वर्षीय दौलत कंवर ने कहा, "मेरा बेटा एक अंग्रेजी माध्यम स्कूल में पढ़ता है और मैं कंप्यूटर के बारे में अधिक नहीं जानती थी।" इस प्रशिक्षण ने मूल बातें सीखने में मेरी सहायता की है। "मैं और अधिक सीखना चाहती हूँ और गाँव स्तर पर नौकरी पाने के लिए उचित प्रमाणन प्राप्त करना चाहती हूँ," उन्होंने आगे कहा ।[11]

2. **यशोदा एआई—आपकी एआई सखी: राष्ट्रीय स्तर की पहल -** राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) ने 24 मई 2025 को 'यशोदा एआई—योर एआई सखी' नामक एक नवीन पहल शुरू की. इसका उद्देश्य महिलाओं, खासकर ग्रामीण और अर्ध-शहरी समुदायों की महिलाओं को कृत्रिम बुद्धि, साइबर सुरक्षा और डिजिटल सुरक्षा में आवश्यक कौशल प्रदान करना था।[12]

NCW की अध्यक्ष विजया राहटकर ने कहा, "वास्तविक परिवर्तन तब शुरू होता है जब एक महिला भविष्य के उपकरणों में महारत हासिल कर लेती है।" यशोदा एआई अभियान केवल प्रौद्योगिकी सीखने के बारे में नहीं है; यह आत्मविश्वास पैदा करता है, सही निर्णय देता है और हर महिला को एक सुरक्षित और समावेशी डिजिटल कल बनाने के लिए सशक्त बनाता है। यह अभियान AI-संचालित अपराधों, डिजिटल गोपनीयता और व्यावहारिक सुरक्षा रणनीतियों पर विस्तृत चर्चा करता है। यह सामुदायिक-संचालित डिजिटल शिक्षा पर जोर देता है और विद्यार्थियों, शिक्षकों और पुलिस बल में महिलाओं के साथ सक्रिय सहयोग का लक्ष्य रखता है ।[13]

विद्यालयों और कॉलेजों में यह कार्यक्रम लागू किया जाएगा, जिसका लक्ष्य स्वयं सहायता समूह (SHG) सदस्यों, आशा कार्यकर्ताओं, शिक्षकों, सरकारी कर्मचारियों, पंचायत प्रतिनिधियों सहित विभिन्न महिलाओं के समूहों को जोड़ना है। प्रशिक्षित महिलाएँ डिजिटल इंडिया मिशन में महत्वपूर्ण योगदान देने की उम्मीद है और डिजिटल युग में अपने परिवारों को मार्गदर्शन देंगी ।[14]

3. **मध्य प्रदेश: मंडला जिले की ऐतिहासिक उपलब्धि -** मंडला जिला, मध्य प्रदेश, जनवरी 2026 में 100 प्रतिशत डिजिटल साक्षरता हासिल करने वाला पहला जिला था ।[15] स्थानीय संस्थाओं और सरकारी निकायों के सहयोग से लक्षित प्रशिक्षण कार्यक्रमों ने डिजिटल विभाजन को दूर किया। यह सफलता दिखाती है कि केंद्रित हस्तक्षेप हाशिए के समुदायों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति को सुधार सकता है।

4 . **10 लाख नागरिकों के लिए मुफ्त AI प्रशिक्षण -** केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि जुलाई 2025 में सभी ग्राम स्तरीय उद्यमियों (VLEs) को AI प्रशिक्षण मुफ्त में मिलेगा। वैष्णव ने मेघालय की रोज़ एंजेलीना और मयूरभंज जिले की VLE मंजुलता की प्रेरक कहानियों का हवाला दिया। महिला VLE रोज़ एंजेलीना एम. खरसिंथ्यू ने मेघालय के पूर्वी और पश्चिमी खासी हिल्स की सुंदर पहाड़ियों और दूरदराज के गाँवों के बीच एक डिजिटल क्रांति लिखी है। उन्होंने कहा कि मैरांग क्षेत्र में अपने केंद्र के माध्यम से वह न केवल सेवाएँ प्रदान कर रही है, बल्कि परिवर्तन, सशक्तिकरण और सामुदायिक सेवा का एक उदाहरण स्थापित कर रही है।[16]

नीतिगत सिफारिशें और भविष्य का मार्ग :

1. **लिंग-उद्देश्यपूर्ण डिजिटल कौशल कार्यक्रम -** LEAD रिपोर्ट ने बुनियादी से लेकर उन्नत डिजिटल कौशल कार्यक्रमों की वकालत की, जो सुनिश्चित करते हैं कि महिलाएँ कम-कौशल वाले कामों तक नहीं सीमित रहें।
2. **सुरक्षित और किफायती डिजिटल बुनियादी ढाँचा -** रिपोर्ट डिजिटल बुनियादी ढाँचे के विस्तार की जरूरत पर बल देती है, जिसमें डिवाइस, विश्वसनीय कनेक्टिविटी और स्थानीय भाषा सामग्री तक पहुँच शामिल हैं। ताकि ऑनलाइन उत्पीड़न, धोखाधड़ी और सामग्री-संबंधी खतरे का मुकाबला किया जा सके, सुरक्षा और विश्वास तंत्र को मजबूत किया जाना चाहिए।
3. **समावेशी AI डिजाइन -** रिपोर्ट कहती है कि महिला कर्मचारियों के लिए उचित वेतन और मान्यता सुनिश्चित करने के लिए डिजिटल कार्य मॉडलों में AI और डेटा पारिस्थितिकी तंत्रों में समावेशी डिजाइन की जरूरत है।[17]
4. **वित्तीय साक्षरता और जागरूकता -** लक्षित वित्तीय साक्षरता कार्यक्रमों की जरूरत है ताकि वित्तीय समावेशन में सूचना की कमी दूर हो सके। इन कार्यक्रमों का उद्देश्य महिलाओं को बैंकिंग उत्पादों, बचत योजनाओं और निवेश विकल्पों के बारे में जानकारी देना होना चाहिए, ताकि वे सही वित्तीय निर्णय ले सकें।[18]
5. **सामुदायिक भागीदारी को मजबूत करना -** यशोदा एआई और कंप्यूटर सखी की सफलता दिखाती है कि सामुदायिक भागीदारी डिजिटल सशक्तिकरण की कुंजी है। घर-घर, मोहल्ले-मोहल्ले में सामुदायिक स्वयंसेवकों, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, शिक्षकों और स्थानीय नेताओं को मजबूत करना चाहिए।

निष्कर्ष: डिजिटल इंडिया अभियान ने भारत का डिजिटल परिदृश्य निश्चित रूप से बदल दिया है। भारत डिजिटल रूप से सशक्त समाज बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है, जैसे कि सीएससी का विस्तार, यूपीआई क्रांति और मुफ्त AI प्रशिक्षण की घोषणा। हालाँकि, डिजिटल विभाजन अभी भी है, खासकर महिलाओं में। ग्रामीण महिलाओं में मोबाइल स्वामित्व और इंटरनेट उपयोग की कम दर, वेतन असमानता और डिजिटल वर्कफोर्स में महिलाओं का कम प्रतिनिधित्व जैसे मुद्दों को हल करना आवश्यक है।

Journal of Research and Development
A Multidisciplinary International Level Referred and Double Blind Peer Reviewed, Open Access
ISSN : 2230-9578 | Website: https://jrdrvb.org Volume-18, Issue-3(A)| March-2026

यह अच्छा है कि महिलाएँ उधारकर्ता, बचतकर्ता और लक्ष्य-उन्मुख निवेशक हैं। मंडला जिले की सफलता, कंप्यूटर सखी और यशोदा एआई की सफलता जैसी स्थानीय पहलें दिखाती हैं कि लक्षित हस्तक्षेपों से बदलाव लाया जा सकता है। महात्मा गांधी ने कहा, "यदि आप दुनिया में वह बदलाव देखना चाहते हैं, तो स्वयं वह बदलाव बनिए।" यह बदलाव हर व्यक्ति से शुरू होता है, डिजिटल इंडिया के इस दशक में—हर महिला जो डिजिटल उपकरण सीखती है, हर बेटी जो ऑनलाइन शिक्षा प्राप्त करती है, हर ग्राम स्तरीय उद्यमी जो CSC चलाता है, हर "AI सखी" जो अपने समुदाय को मार्गदर्शन करता है। विकसित भारत बनाने के लिए डिजिटल क्रांति समावेशी होनी चाहिए. ऐसी डिजिटल अर्थव्यवस्था में महिलाएँ न सिर्फ उपभोक्ता हों, बल्कि इसके निर्माता, नेता, और निर्णायक भी हों। यह वास्तविक डिजिटल सशक्तिकरण है और यह डिजिटल इंडिया का अंत होना चाहिए।

संदर्भ सूची

1. कॉमन सर्विस सेंटर ई-गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड (CSC SPV), (2025, 16 जुलाई), 10 Years of Digital India Celebration. नई दिल्ली: इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, ऑनलाइन,पृ. 1
2. गांधी, मोहनदास करमचंद (1940), हरिजन (संपादकीय), अहमदाबाद: नवजीवन प्रकाशन मंदिर, पृ. 122
3. कॉमन सर्विस सेंटर ई-गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड (CSC SPV), (2025, 16 जुलाई), 10 Years of Digital India Celebration. नई दिल्ली: इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, ऑनलाइन, पृ. 1
4. वही
5. नेशनल ई-गवर्नेंस डिवीजन (NeGD). (2025, 26 अगस्त), Digital India Awareness University Workshop cum Digital India Talk Show at Lady Shri Ram College for Women. नई दिल्ली: इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, ऑनलाइन,पृ. 1
6. फ्री प्रेस जर्नल (2026, 13 जनवरी), UP CM Yogi Adityanath's initiative strengthens digital education for girls. मुंबई: फ्री प्रेस जर्नल, ऑनलाइन,पृ. 1
7. रेडसीर स्ट्रैटेजी कंसल्टेंट्स (2026, 5 मार्च), 7.5 crore working women can unlock Rs 2.8 lakh crore opportunity for BFSI sector in India (आईएएनएस रिपोर्ट), नई दिल्ली: रेडसीर स्ट्रैटेजी कंसल्टेंट्स, ऑनलाइन,पृ. 1
8. वही
9. लीड (LEAD) एट क्रिया यूनिवर्सिटी (2025, 13 नवंबर), Decoded: Women and the Future of Digital Work in India (चर्चा 2025 में जारी रिपोर्ट), नई दिल्ली: क्रिया विश्वविद्यालय अनुसंधान केंद्र / द/नज इंस्टीट्यूट, ऑनलाइन, पृ. 1
10. वही
11. ब्यूरोक्रेट्स इंडिया (2026, 31 मार्च), 'Computer Sakhi' to educate rural women of Churu district in Rajasthan. जयपुर: ब्यूरोक्रेट्स इंडिया, ऑनलाइन,पृ. 1
12. उस्थादियन अकादमी (2025, 25 मई), Yashoda AI empowering women in digital India. उस्थादियन अकादमी करेंट अफेयर्स, ऑनलाइन, पृ. 1
13. देवएक्स (2025, 2 जून), NCW launches Yashoda AI to empower women. देवएक्स डेली न्यूज़, पृ. 1
14. उस्थादियन अकादमी (2025, 25 मई), Yashoda AI empowering women in digital India. उस्थादियन अकादमी करेंट अफेयर्स, ऑनलाइन,पृ. 1
15. टेस्टबुक (2026, 8 फरवरी), Which district of Madhya Pradesh achieved 100% "Digital Literacy" among its tribal women population in January 2026?, ऑनलाइन, पृ. 1
16. प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो, भारत सरकार (2025, 16 जुलाई), 10 Lakh Citizens to Receive Free AI Training: Priority will be given to Village Level Entrepreneurs (VLEs) (प्रेस विज्ञप्ति). नई दिल्ली: इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, ऑनलाइन, पृ. 1
17. लीड (LEAD) एट क्रिया यूनिवर्सिटी (2025, 13 नवंबर), Decoded: Women and the Future of Digital Work in India (चर्चा 2025 में जारी रिपोर्ट), नई दिल्ली: क्रिया विश्वविद्यालय अनुसंधान केंद्र / द/नज इंस्टीट्यूट, ऑनलाइन,पृ. 1
18. रेडसीर स्ट्रैटेजी कंसल्टेंट्स (2026, 5 मार्च), 7.5 crore working women can unlock Rs 2.8 lakh crore opportunity for BFSI sector in India (आईएएनएस रिपोर्ट). नई दिल्ली: रेडसीर स्ट्रैटेजी कंसल्टेंट्स, ऑनलाइन, पृ. 1